भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3449
दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

बाल विकास परियोजनाओं में रिक्तियां

3449. **श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चंद्रपुर, महाराष्ट्र में बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के 15 में से 14 पद और पर्यवेक्षिका के 89 में से 23 पद रिक्त हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार इसे बाल विकास योजनाओं के प्रशासनिक कार्यान्वयन में एक गंभीर त्रुटि मानती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त रिक्तियों का एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अंतर्गत सेवाओं की गुणवत्ता और व्यापकता तथा बच्चों और माताओं को नियमित देखभाल और सेवाएँ प्रदान करने पर क्या प्रभाव पड़ता है;
(घ) क्या चंद्रपुर में 2447 आंगनबाड़ी सेविका पदों में से 71 और 2447 सहायिका पदों में से 118 रिक्त हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंगनवाड़ी केंद्रों के दैनिक कार्यकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है; और
(ङ) निश्चित योजना और समय-सीमा सहित सीडीपीओ, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सरकार द्वारा उठाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि चंद्रपुर जिला परिषद में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना परियोजनाओं के अंतर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारी

(समूह ख) के 15 स्वीकृत पदों में से 14 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों के 89 स्वीकृत पदों में से 30 रिक्त हैं।

आईसीडीएस सेवाओं की गुणवत्ता और व्यापकता में गिरावट से बचाने के लिए, रिक्त पदों की ज़िम्मेदारी अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंपी गई है। इन माध्यमों से माताओं और बच्चों को नियमित सेवाएं और देखभाल प्रदान की जा रही है।

जिला परिषद चंद्रपुर की 15 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना परियोजनाओं में स्वीकृत 2,447 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के पद में से 69 पद रिक्त हैं तथा स्वीकृत 2,447 आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पद में से 154 पद रिक्त हैं।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति और आयोजन के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों को भरने का मामला संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस मुद्दे को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ निरंतर संवाद/वीडियो कॉन्फ्रेंस और बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से उठाया जाता है।

****